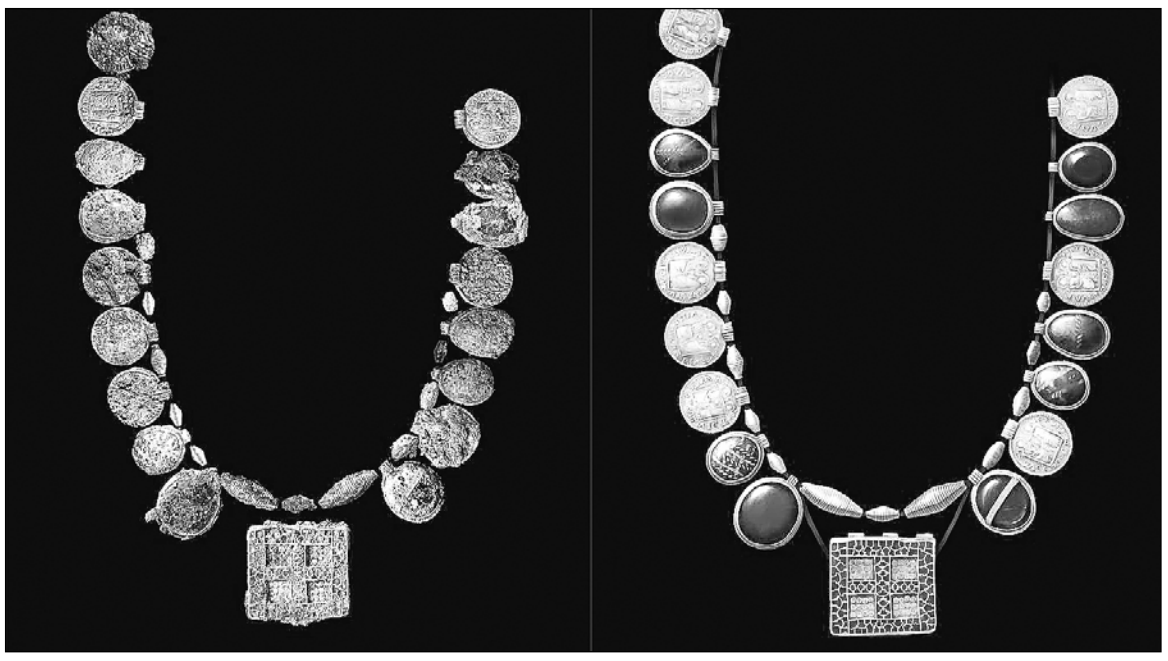

पुरातत्वविदों को इंगलैंड के नॉर्थैम्पटनशायर में एक मकान के लिए खुदाई के दौरान 1300 साल पुराना हार मिला है। म्यूज़ियम ऑफ लंदन आर्किऑलजी (एम.ओ.एल.ए.) के शोधकर्ता कहते हैं कि, ब्रिटेन में मिले इस तरह के हारों में यह सबसे शानदार और कीमती है। इसमें रोमन सिक्कों, सोना, गार्नैट, कांच और कई सैमिप्रेशस स्टोन्स से बने मनके व 30 पैन्डैन्ट हैं। यह हार एक ऊंचे तबके की महिला की कब्र में मिला है। कब्र में अन्य वस्तुएं भी मिली हैं, जिनकी जांच हो रही है। इस संग्रह को ''हारपोल ट्रैज़र'' नाम दिया गया है। विशेषज्ञों को यकीन है कि, यह ब्रिटेन में अब तक खोजी गई किसी भी महिला की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कब्र है। एम.ओ.एल.ए. साइट सुपरवाइज़र लैवैंत बैंसे बालाश ने कहा, ''जब मिट्टी से सोना झांकने लगा तो हम जान गए कि कुछ महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें यह अनुमान भी नहीं था कि यह खोज इतनी खास होने वाली है। चौकोर पैन्डैंट इस हार का सैंटर पीस है जिसके ऊपर क्रॉस बना हुआ है। स्वर्ण में जड़ा यह पैन्डैंट रैड गार्नैट से बना है। विशेषज्ञों का मत है कि, यह मूलतः एक मुड़े हुए क्लास्प (बकसुआ) का आधा भाग रहा होगा जिसे पैन्डैंट के रुप में पुनः प्रयुक्त किया गया। यहां एक कलात्मक क्रॉस भी मिला है, जिस पर चाँदी में बने मनुष्य के चेहरों को असामान्य रुप में दर्शाया गया है। हार को देखकर लगता है कि यह किसी इसाई महिला मठाध्यक्ष का रहा होगा। कब्र में जो शव था वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, बस टूथ एलैमल के कुछ अंश बचे हैं। हारपोल ट्रैज़र संकेत देता है कि यह ऊंचे तबके की धार्मिक महिला रही होगी। विशेषज्ञ आधुनिक तरीकों से खोज में मिले सामान का और आसपास की जगह का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि उक्त महिला और उसके अंतिम संस्कार के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सके। शोधकर्ता, इस हार और कब्र में मिले कार्बनिक अवशेषों का उद्गम पता लगाने का प्रयास कर रहे है। इंगलैंड के कई अन्य क्षेत्रों में ऐसे ही कुछ हार मिल चुके हैं पर कोई भी इतना कलात्मक नहीं है। हारपोल ट्रैज़र बी.बी.सी. के ''डिगिंग फॉर ब्रिटेन'' शो में 23 जनवरी को प्रदर्शित किया जाएगा।

नेपाल में रेल लाइन बिछाने की होड़ में चीन से आगे निकला भारत

नई दिल्ली, 21 जनवरी। भारत ने नेपाल में चीन की बिछी-बिछाई बाजी पलट दी है।

चीन, भारत के खिलाफ नेपाल को लगातार प्रलोभन देता रहता है। चीन केरुंग-काठमांडू रेलवे लाइन बिछाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन भारत ने बाजी पलट दी है। रक्सौल-काठमांडू रेल लाइन के लिए भारत ने फाइनल लोकेशन सर्वे तेज कर दिया है। इससे चीन ठगा सा रह गया है। भारत के ऐक्शन में आने से चीन भी उठापटक में

- **चीन, नेपाल में रेल लाइन की बिछाने की शुरुआती चरण में है तथा भारत ने काठमांडू तक रेल चलाने का काम फाइनल स्टेज तक पहुँचा दिया है।**

जुट गया है और उसने अपनी चाल को तेज कर दिया है।

चीन ने अब केरुंग-काठमांडू रेलवे लाइन की संभावना की जांच के लिए अध्ययन शुरू कर दिया है। ड्रैगन की चाल में यह तेजी के.पी. ओली के समर्थन वाली प्रचंड सरकार के सत्ता में आने के बाद आई है। हालांकि भारत के रक्सौल-काठमांडू रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे तेज होने के बाद हमारा काठमांडू तक रेल चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को सस्पैंड किया गया

विनोद तोमर ने बृजभूषण सिंह के समर्थन में बयान देकर उनके खिलाफ लगे आरोपों को निराधार बताया था

- **विनोद तोमर ने शनिवार सुबह अपने बयान में था कि, मैं बृजभूषण सिंह के साथ गत 12 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने इस प्रकार की कोई गलती नहीं की है।**
- **विनोद तोमर ने कहा कि, पहलवान तीन-चार दिन से केवल आरोप ही लगा रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया है।**

नई दिल्ली, 21 जनवरी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर को शनिवार (21 जनवरी) को सस्पैंड कर दिया है। विनोद तोमर ने सुबह में ही में कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में बयान दिया था। विनोद तोमर का मानना है कि बृजभूषण शरण सिंह ने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा था, आरोप निराधार हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तीन-चार दिन हो गए हैं और उन्होंने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है। मैं पिछले 12 सालों से उनके साथ जुड़ा हुआ हूं और मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा।

विनोद तोमर ने आगे कहा था, जब तक जांच जारी है तब तक उन्होंने खुद को अलग रखा है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जांच समाप्त होने तक भारतीय कुश्ती संघ की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से खुद को दूर कर लिया है ताकि जांच प्रभावित न हो।

भारत के 30 से ज्यादा पहलवानों ने बुधवार के दिन दिल्ली के जंतर-मंतर में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया था और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि, बृजभूषण ने इस आरोपों को सिरे से खारिज किया और पहलवानों पर आरोप लगा दिए। बृजभूषण के आरोपों का पहलवानों पर कोई असर नहीं पड़ा और प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच खेल मंत्रालय और कुश्ती संघ ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रहीं। पहलवान अपनी मांग पर अड़े रहे। अंत में पहलवानों के सामने बृजभूषण के दांव पेंच कमजोर पड़ गए और उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया।

बुधवार सुबह शुरू हुआ प्रदर्शन तीन दिन तक चला शुक्रवार रात पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बात की और बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया और उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच के लिए समिति बना दी गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक्शन मोड में

- **प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से पहले 8 जिला अध्यक्षों को बदला**
- **गौरतलब है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में चुनाव वाले राज्यों में संगठनात्मक फेरबदल की संभावना व्यक्त की गई थी।**

जयपुर, 21 जनवरी (का.सं.)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब एक्शन मोड में आ गये हैं। दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से लौटने के तुरंत बाद से पूनिया ने अपने क्रियाकलाप और संगठन से संबंधित कामकाज और तेज कर दिये हैं।

पिछले दिनों सतीश पूनिया ने जिलों की अंदरूनी रिपोर्ट के लिए जिला पर्यवेक्षक लगाए थे। उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक जिलाध्यक्ष में बदलाव किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कई जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ने के मूड में है उसके कारण भी इनको बदला गया है।

इसके साथ ही बीकानेर शहर के लिए विजय आचार्य को जिलाध्यक्ष तथा बीकानेर देहात जालम सिंह भाटी, अलवर उत्तर उम्मेद सिंह भाया, अलवर दक्षिण अशोक गुप्ता, भरतपुर से ऋषि बंसल, सवाई माधोपुर सुनील दीक्षित, बाड़मेर में स्वरूप सिंह खारा, बालोतरा में बाबू सिंह राजगुरु को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इतना ही नहीं स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि संगठन में निष्क्रिय रहे जिलाध्यक्षों को भी बदला जायेगा? चर्चा है कि, पिछले कई दिनों से निष्क्रिय पड़े प्रदेश पदाधिकारियों एवं प्रदेश के जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा।

मिस्र के राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अल-सिसी प्रधानमंत्री मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। इसके अलावा, वे व्यवसायी-समुदाय के साथ भी संवाद करेंगे। उनके साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आयेगा जिसमें मिस्र के पाँच मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

नंद्राजोग कमेटी करेगी पूर्व खेतड़ी महाराज की संपत्तियों की निगरानी

- **सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी महाराज की हैरिटेज सम्पत्ति की देखभाल के लिए रिटायर्ड जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है।**
- **जस्टिस प्रदीप नंद्राजोग राजस्थान व बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर कलैक्टर को अवमानना नोटिस भी जारी किया, क्योंकि उन्होंने हैरिटेज सम्पत्ति को कब्जे में लेने के आदेश का पालन नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हैरिटेज सम्पत्तियों से सभी कब्जे 6 सप्ताह में हटाने के आदेश भी दिए।**

जयपुर, 21 जनवरी। सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी के महाराज सरदार सिंह की करोड़ों रुपए की हेरिटेज संपत्तियों से जुड़े मामले में राजस्थान और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व सीजे प्रदीप नंद्राजोग की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। इसमें हेरिटेज आर्किटेक्ट और आर्कियोलॉजीकल सर्वे आफ इंडिया के सदस्य भी शामिल होगें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर कलैक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया, क्योंकि अदालती आदेश की पालना के तहत उन्होंने हेरिटेज संपत्तियों की देखरेख के लिए उन्हें अपने कब्जे में नहीं लिया।

सुनवाई के दौरान खेतड़ी ट्रस्ट ने एक खोए हुए खजाने के नाम से एक बुकलेट पेश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेरिटेज संपत्तियों की मरम्मत और देखरेख में राज्य सरकार उदासीन लग रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पांच करोड़ रुपए का बजट देने पर खुशी जताई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस नंद्राजोग के लिए फिलहाल एक लाख रुपए प्रति विजिट या सिटिंग तय की है, लेकिन इस फीस में काम के अनुसार बदलाव हो सकेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने खेतड़ी के पूर्व महाराजा की हेरिटेज संपत्तियों पर हो रहे कब्जों को छह सप्ताह में हटाने के निर्देश देते हुए किसी भी अन्य कोर्ट में इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करने का आदेश दिया है। साथ ही भविष्य के अतिक्रमण रोकने के लिए जिला कलेक्टर को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा है।

अदालत ने पूर्व सीजे की कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 मार्च तय की है।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खेतड़ी महाराज की संपत्ति पर सरकारी कब्जे की कार्यवाही को गैर-कानूनी घोषित करते हुए वापिस लौटाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है।

राष्ट्रपति मुर्मू पुराने संसद भवन में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जनवरी। नये संसद भवन का निरीक्षण करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति मुर्मू 31 जनवरी को वर्तमान संसद भवन के सैन्ट्रल हॉल में लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। उनका कहना है कि नया संसद भवन अभी निर्माणाधीन है।

सरकार शीतकालीन सत्र नये भवन में नहीं चला सकी थी लेकिन ऐसी कोशिश की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को नये लोकसभा भवन में ही बजट प्रस्तुत करें।

केन्द्र ने शुक्रवार को निर्माणाधीन संसद भवन के नये फोटो जारी किये भवन को फिनिशिंग टच देने का काम चल रहा है। यह सैन्ट्रल विस्टा का हिस्सा है, जिसमें विशाल हॉल, आधुनिक पुस्तकालय, पुनर्विकसित कार्यालय तथा कमेटी कक्ष आदि स्टेट-ऑफ-आर्ट सुविधाओं से युक्त होंगे।

- **स्पीकर ओम बिड़ला ने ट्वीट में यह जानकारी दी, पर और कहा कि लेकिन कोशिश है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए संसद भवन में बजट प्रस्तुत करे।**

नया संसद भवन वर्तमान संसद भवन से सटा हुआ है। यह करीब 65000 वर्ग मी. क्षेत्र में त्रिकोणीय आकृति में बना हुआ है ताकि जगह का अधिकतम उपयोग हो सके।

मौजदा संसद भवन का उद्घाटन 96 वर्ष पहले, 18 जनवरी को तत्कालीन वामसराय लॉर्ड इर्विन ने किया था। उस समय इसका नाम काउंसिल हाउस था।

प्र.मंत्री मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक सामने आई

नई दिल्ली, 21 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी चूक का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति फर्जी एन.एस.जी. गार्ड बनकर पी.एम. मोदी की रैली में पहुंच गया। उसके पास हथियार भी था। पुलिस को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर जांच की गई। आरोपी के पास एन.एस.जी. का आई.डी. कार्ड बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में एन.एस.जी. से संपर्क किया तब पता लगा कि हिरासत में लिया गया आरोपी नकली सैनिक है। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

मामला गुरूवार का है। पी.एम. नरेंद्र मोदी मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) पहुंचने वाले थे। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चेतावनी जारी की हुई थी। जिसके बाद सुरक्षाबल अतिरिक्त सावधानी बरत रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने ख़ुद को पहले सेना का ''गार्ड्स रेजिमेंट'' से नाइक होने का दावा करते हुए उच्च सुरक्षा वाले वी.वी.आई.पी. क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की जब पुलिस ने उसे शक की बुनियाद पर रोका तो उसने खुद को एन.एस.जी. का अधिकारी बताया। इसके लिए उसने बाकायदा एन.एस.जी. का एक आई.डी. कार्ड भी दिखाया, लेकिन उसकी हरकते संदिग्ध थी। पुलिस ने एन.एस.जी. को इसकी सूचना दी तो एन.एस.जी. ने रामेश्वर मिश्रा के एन.एस.जी. से किसी तरह का संपर्क होने से इनकार कर दिया।

गिरफ़्तार आरोपी की जांच पड़ताल में पता चला कि रामेश्वर मिश्रा नवी मुम्बई में रहता है और उसने साइंस से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। आरोपी रामेश्वर मिश्रा पर अब धारा 171,465,468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को शुक्रवार को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने उसे 24 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

भारत सरकार ने यू-ट्यूब व ट्विटर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्वीट्स को और उन्हें ब्लॉक कर दे।

सुविज्ञ सूत्रों ने पुष्टि की है कि विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों के सीनियर अधिकारियों ने डॉक्यूमैन्टरीका परीक्षण कर पाया कि यह भारत के विभिन्न समुदायों में विभाजन के बीज बोने के अलावा भारत के सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता और प्राधिकार को कटकरे में खड़ा करने का एक प्रयास है।

सूत्रों ने बताया कि डॉक्यूमैन्टरी को भारत की संप्रभुता और अखंडता को कम करने वाला पाया गया तथा यह भी यह देश की सार्वजनिक व्यवस्था और विदेशों के साथ देश के दोस्ताना संबंधों पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। इस बीच सेवानिवृत्त जजों और नौकरशाहों सहित कुल 302 हस्ताक्षरकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बनी बी.बी.सी. की इस डॉक्यूमैन्टरी की एक बयान में आलोचना की है। सशस्त्र सेनाओं के सीनियर्स भी बयान के सह-हस्ताक्षरकर्ता हैं।

सूत्रों ने बताया कि प्रिंट, ऑडियो-वीडियो और सोशल मीडिया का कामकाज देखने वाले सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा के विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह बी.बी.सी. की इस डॉक्यूमैन्टरी के कन्टैन्ट्स पर पलटवार करने के लिए रात-दिन एक कर दें।

विदेश मंत्रालय ने इस डॉक्यूमैन्टरी के लिए कल ही कहा था कि यह एक दुष्प्रचार है और उद्देश्य विहीन है तथा इसमें औपनिवेशिक मन:स्थिति की झलक दिखलाई देती है। मंत्रालय ने विदेशों में स्थित अपने दूतावासों से कहा है कि वे इस डॉक्यूमैन्टरी के कारण होने वाली किसी भी नकारात्मकता का मजबूती से विरोध करे। सत्तारूढ़ पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि ''भाजपा शासित सरकार अथवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कोई भी आलोचना दुष्प्रचार है, जबकि दोनों की प्रशंसा करना एक निष्पक्ष पत्रकारिता है।'' यह एक नई परिभाषा है जिस पर केन्द्र सरकार वर्तमान में कार्य कर रही हैं।

कांग्रेस सांसद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गहलोत पायलट को नकारा निकम्मा और गद्दार तक कह चुके हैं।

हालांकि अब तक शांत रहने वाले सचिन पायलट ने भी गहलोत के बयानों का सधे हुए शब्दों में जवाब देते हुए कहा है कि ''मैंने मेरे स्वर्गीय पिताजी से राजनीति में बहुत कुछ देखा और सीखा है। मैंने उन्हें राजनीति के अखाड़े में बड़ों-बड़ों को पटकनी देते हुए देखा है। मुद्दों पर, पब्लिक सेंटीमेंट पर आप खड़े हों तो लोग ताली बजाते हैं। अपमान कर देना, छोटी-मोटी बात बोल देना, अच्छी बात नहीं है। आप सब जानते हो कि मेरे बारे में क्या- क्या बोला गया है।

अप्रैल से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रीमियम ट्रेनें प्लेटफॉर्म नम्बर 6 से 16 तक चलेंगी। अन्य सुपरफास्ट, मेल, एक्सप्रैस, इन्टरसिटी तथा पैसेन्जर ट्रेनें नई दिल्ली की बजाय पुरानी दिलली स्टेशन से चलेंगी तथा कुछ अन्य ट्रेन गाजियाबाद, फरीदाबाद, तिलक ब्रिज, सफदरजंग, दिल्ली छावनी तथा अन्य छोटे स्टेशनों से चलेंगी।

रेलवे ने सी.पी.डब्ल्यु.डी. को पत्र लिख दिया है कि वह इन स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा कर दे ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके तथा यात्री इससे प्रभावित न हों।

इसके अलावा, रेलवे राष्ट्रीय राजधानी के तीन स्टेशनों- नई दिल्ली, आनन्द विहार तथा निज़ामुद्दीन पर प्रीमियम एग्ज़ीक्यूटिव वेटिंग लाउन्ज शुरु कर रहा है। इनमें से पहले लाउन्ज (निज़ामुद्दीन स्टेशन) ने इस सप्ताह से काम करना शुरु कर दिया। इसका शुल्क दो घंटे के लिये 150 रू. तथा इसके बाद हर अतिरिक्त घंटे के लिये 50 रू. घंटा होगा।

निक्की हेली 2024 के राष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने की सोचते हैं तब आप दो तथ्यों पर गौर करते हैं। पहला तो यह कि क्या वर्तमान स्थिति के मद्देनज़र नए नेतृत्व की जरूरत है? और दूसरा यह कि क्या मैं ही वह व्यक्ति हूं जो नया नेता बन सकता है। लेकिन, हां, हमें एक नई दिशा में जाने की जरूरत है? और क्या मैं वह नेता हो सकती हूं? हां! मैं समझती हूं कि मैं वह नेता हो सकती हूं।''

हेली, जिन्होंने अक्टूबर 2018 में ट्रम्प प्रशासन से इस्तीफा दे दिया था, ने कहा कि उन्होंने गवर्नर तथा राजदूत के पद पर बहुत ही अच्छा काम किया था।

उन्होंने कहा, ''गवर्नर के रूप में मैंने एक ऐसा पीड़ित राज्य हाथ में लिया था, जहाँ बेरोजगारी दो अंक में थीं और हमने उसे सर्वश्रेष्ठ बना दिया था। राजदूत के रूप में जब उन्होंने हमारा अनादर करने की कोशिश की तो हम दुनिया से रूबरू हुये। मेरा मानना है कि मैंने यह सिद्ध कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हम कितने सक्षम है तथा हम क्या कर सकते हैं।

हेली ने कहा, ''इस प्रकार मैं सोचती हूँ कि मैं नेता बन सकती हूँ। लेकिन अभी हम विचार कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिये तथा उस कार्य विशेष की तलाश में हैं। मैं कभी कोई दौर हारी नहीं हूँ। मैंने यह उस समय भी कहा था और मैं यह अब भी कह रही हूँ। मैं हारने वाली नहीं हूँ तथा मैदान में डटी हुई हूँ।

हेली, जो भारतीय मूल की दूसरी गवर्नर रहीं, ने कहा कि अब रिपब्लिकन पार्टी में नये नेतृत्व को लाने का समय आ गया है। ज्ञातव्य है कि भारतीय मूल के पहले गवर्नर रिपब्लिकन बॉबी जिंदल थे जो लूसिआना के गवर्नर रहे थे।

हेली ने कहा, हमने राष्ट्रपति पद के लिये आठ में से अंतिम सात वोट गँवा दिये हैं। आठ में से सात रिपब्लिकन हार गये। यानी, कहीं कुछ गलत तो है। और इसलिये मैं सोचती हूँ कि हम पार्टी में नई पीढ़ी को लाएं। नई पीढ़ी ही नये लोगों को पार्टी से जोड़ सकती है तथा उस स्थिति में पार्टी उन समाधानों के बारे में बात कर सकती है, जिनकी हमें जरूरत है।

इन्टरव्यू के दौरान, हेली ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रपति बाइडन, जो डैमोक्रेट हैं, को दूसरा कार्यकाल नहीं दिया जाना चाहिए। अस्सी वर्षीय बाइडन अमेरिका के सर्वाधिक उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। हेली ने कहा, ''अगर मैं चुनाव लड़ूँगी तो जो बाइडन के खिलाफ ही चुनाव लड़ूंगी। मेरा पूरा फोकस इसी बिन्दू पर है क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो बाइडन दूसरी बार राष्ट्रपति बनें।''

एफ.आई.आर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राइट टू इन्फॉर्मेशन (आर.टी.आई.) के अन्तर्गत जानकारी देने पर जोर दिया गया था।

जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की सुप्रीम कोर्ट की एक बैंच ने याचिका को सुनवाई के योग्य ना पाते हुए इस आधार पर निरस्त कर दिया कि एफ.आई.आर. को एविडैन्स एक्ट की परिभाषा के अन्तर्गत एक सार्वजनिक दस्तावेज नहीं माना जा सकता क्योंकि यह एक निजी दस्तावजे है। कोर्ट ने कहा कि यदि एफ.आई.आर. और संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए या वैबसाइट्स पर डाला जाए तो इससे आरोपी और पीड़ित और जांच एजेंसी तक के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

- **सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि, एफ.आई.आर. व चार्जशीट को सार्वजनिक करने से आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों का हनन होता है।**

'संघ द्वारा नेताजी के जन्मदिवस पर भारी आयोजन...

- **मुंबई में प्र.मंत्री मोदी की सुरक्षा में तैनात होने हथियार के साथ पहुँचा नकली एन.एस.जी. गार्ड।**

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आर.एस.एस. प्रमुख मोहन भागवत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयन्ती को स्मरणोत्सव के रूप में मनाने के लिये कोलकाता में शहीद मीनार पर एक सार्वजनिक आयोजन को संबोधित करेंगे।

बोस-प्लाफ ने कहा कि भाजपा और आर.एस.एस. सभी धर्मों का सम्मान करने के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जैसा कि नेताजी सिखाया करते थे। उन्होंने कहा कि नेताजी एक धर्मपरायण हिन्दू थे लेकिन वे अन्य सभी धर्मों का सम्मान करने में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा कि वे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सृजनात्मक एवं उत्पादक सहयोग के पक्षधर थे।

उन्होंने जर्मनी, जहाँ वे रहती हैं, से समाचार एजेंसी पी.टी.आई. को बताया, ''आर.एस.एस. और भाजपा इस प्रवृत्ति को निश्चित रूप से नहीं दर्शाते।..... अगर आप सामान्य लेबल लगाने की भाषा में बात करें तो ये (आर.एस.एस. एवं भाजपा) दक्षिणपंथी हैं तथा नेताजी वामपंथी थे।''

बोस-प्लाफ ने कहा, ''आर.एस.एस. की विचारधारा के बारे में जो कुछ मैंने सुना है, मैं इस बात के प्रति सहमति व्यक्त करना चाहूँगी कि इनकी विचारधारा और नेताजी की विचारधारा एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। दोनों के जीवन मूल्य परस्पर मेल नहीं खाते। अगर आर.एस.एस. ऐसा कहती है, तो मुझे निश्चित रूपसे बहुत अच्छा लगता। अनेक तथा विभिन्न ग्रुप भिन्न तरीकों से नेताजी की जयन्ती मनाना चाहते हैं तथा उनमें से बहुत से ग्रुप निश्चित रूप से नेताजी के विचारों से सहमत हैं।'' उन्होंने इस बात के प्रति अपनी सहमति व्यक्त की कि उनके पिता की जयन्ती के बड़े पैमाने पर एवं धूमधाम से मनाया जाने का उद्देश्य ''आंशिक रूप से उनकी विरासत का दोहन अर्थात् अनुचित लाभ उठाना'' है।

उनसे पूछे जाने पर कि क्या नेताजी आर.एस.एस. के आलोचक थे, उन्होंने कहा, ''मुझे (नेताजी के) ऐसे किसी कथन की जानकारी नहीं है, जिसे मैं आपको दे सकूँ। हो सकता है कि उन्होंने आर.एस.एस. के सदस्यों के बारे में आलोचनापूर्ण बयान दिय हों। मैं जानती हूँ कि उनके (नेताजी के) विचार आर.एस.एस. के बारे में क्या हैं। दोनों के मूल्य परस्पर मेल नहीं खाते। धर्मनिरपेक्षता को लेकर आर.एस.एस. और नेताजी की विचारधारा एवं सिद्धांतों का आपस में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। नेताजी की जयन्ती पर आयोजित समारोहों की धूमधाम तथा तड़क-भड़क के विषय में बोलते हुये उन्होंने केन्द्र की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की प्रशंसा करते हुये कहा कि वह नेताजी के सम्मान की दिशा में ''कई पहल'' कर रही है।

- **''पर, कांग्रेस ने सदा यह प्रतिपादित किया कि, महात्मा गांधी व कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ही आजादी दिलायी, यह गलत है। सुभाष बाबू के पुराने खत व दस्तावेज प. बंगाल व केन्द्रीय सरकार द्वारा रिलीज़ करने के बाद, यह प्रमाणित हुआ कि, सुभाष बाबू व उनके साथियों द्वारा प्रतिपादित आक्रमणकारी नीतियों व कार्यक्रमों का भी भारी योगदान था, स्वतंत्रता दिलाने में।**

नेताजी की पुत्री ने कहा, ''इसके दो पहलू हैं। आज़ादी के बाद, नेताजी के बारे में कांग्रेस का रुख सुरक्षित तथा किन्तु वे उसका ज्यादा बखान नहीं करते थे। कांग्रेस केवल इसी वृतान्त को कायम रखना चाहती थी कि केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन की बदौलत ही देश को आज़ादी मिली। लेकिन जब नेताजी की फाइलें सामने आईं तो हमें मालूम पड़ा, इण्डियन नैशनल आर्मी (आई.एन.ए.) की आज़ादी में बहुत बड़ी एवं प्रमुख भूमिका रही थी।''

दूसरे पहलू के बारे में बताते हुये, बोस-प्लाक ने यह जानना चाहा कि अगर नेताजी आज जीवित होते तथा उनके विचार वर्तमान सरकार के विचारों से भिन्न होते तो क्या भाजपा उनका सम्मान करती। उन्होंने कहा, ''भाजपा ने नेताजी के सम्मान की दिशा में काफी प्रयास किये हैं। जहाँ तक किसी भी राजनेता का प्रश्न है, आपको सबसे पहले उसकी रूचि तथा हित को देखना होता है। अगर नेताजी आज जीवित होते तथा उनके विचार सरकार के विचारों से भिन्न होते, तो भाजपा ने उन्हें सम्मान नहीं दिया होता। इसलिये (इस प्रकरण में) भाजपा का हित ही साधा जा रहा है।''

तृणमूल कांग्रेस तथा भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनावों से पहले नेताजी की विरासत को अपना बताने के लिए परस्पर खूब संघर्ष किया था। 2015 में, पश्चिम बंगाल सरकार ने गृह विभाग के पास रखी हुई 64 फाइलें मुक्त की थीं। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने इसके अगले साल 100 फाइलें मुक्त कर दी थीं।

आज़ादी के बाद, केन्द्र ने नेताजी के गायब हो जाने के रहस्य को खोलने के लिये तीन जाँच आयोग गठित किये थे।

इनमें से दो आयोग- शाह नवाज़ आयोग तथा खोसला आयोग- कांग्रेस सरकार ने गठित किये थे। ये आयोग इस नतीजे पर पहुँचे थे कि नेताजी की मृत्यु ताइवान के ताइहोकू हवाई अड्डे से 18 अगस्त 1945 को हवाई जहाज उड़ने की शीघ्र बाद ही हुई विमान दुर्घटना में हो गई थी।

तीसरा आयोग- मुखर्जी आयोग- भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार ने गठित किया था, उसने कहा कि उक्त हादसे में नेताजी की मौत नहीं हुई थी।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600